राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4625/2023

जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जेआईईटी), ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मनीष बाफना, रजिस्ट्रार, एनएच -65 पाली रोड, मोगरा, जोधपुर के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, राजस्थान, जयपुर।
2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रक प्राधिकारी, जोधपुर और कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. उपमंडल अधिकारी और उपमंडल मजिस्ट्रेट, लूणी (पीडीआर अधिनियम के तहत प्राधिकारी)।
4. श्रीमती संगीता कोठारी पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश कोठारी, 176, प्रेम नगर, पाल रोड, जोधपुर।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राजेश शाह
प्रतिवादीगण के लिए : श्री संजीव जौहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ललित परिहार के साथ

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

04/11/2024

1. याचिकाकर्ता जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस न्यायालय के समक्ष ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, जयपुर के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.02.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध व्यथित है, जिसके अंतर्गत संयुक्त श्रम आयुक्त (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 03.03.2022 को पारित अर्ध-न्यायिक आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें याचिकाकर्ता संस्थान को प्रतिवादीगण संख्या 4 के पति को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जो रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। याचिकाकर्ता ने

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 12.07.2022 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 03.03.2022 के एकपक्षीय आदेश को खारिज करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 प्रतिवादीगण संख्या 4 के पति राकेश कोठारी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ ग्रेच्युटी भुगतान के लिए निर्देश देने हेतु आवेदन दायर किया। नोटिस जारी किए गए और याचिकाकर्ता को तामील किए गए, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, नियंत्रक प्राधिकारी ने एकपक्षीय कार्यवाही की और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 7(3)(3-ए) के तहत निर्देश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को ब्याज सहित 11,55,375/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

2.2 चूंकि उपरोक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता नहीं चला। इसकी जानकारी होने पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.03.2022 के एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को दिनांक 12.07.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.3. इस बीच याचिकाकर्ता ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8462/2022 के नाम से एक रिट याचिका भी दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 05.07.2022 के आदेश द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी को दिनांक 03.03.2022 के एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिए दायर लंबित आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। उपरोक्त रिट याचिका को दिनांक 13.07.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करके दिनांक 03.03.2022 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी। याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत विद्वान अपीलीय

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)

प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 15.02.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.4 इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादीगण संख्या 4, (मृत कर्मचारी की विधवा) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उनके पति, जो रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे, टर्मिनल कैंसर से असफल रूप से जूझने के बाद मर गए।

4. याचिकाकर्ता-संस्थान की ओर से संबोधित तर्क का सार यह है कि नियंत्रक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता-संस्थान या उसके वकील को सुने बिना दिनांक 03.03.2023 को आपत्तिजनक आदेश पारित किया। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.07.2022 के आदेश के माध्यम से बिना उचित विचार किए इसे बरकरार रखा गया, जिसका यहां भी विरोध किया गया है।

5. मामले के गुण-दोष को देखने के बाद, मैं याचिकाकर्ता-संस्थान द्वारा अपनाए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली बार में, याचिकाकर्ता को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नहीं सुना गया होगा, लेकिन बाद में, उसने विद्वान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया। यह इस तर्क पर आधारित है कि चूंकि अपील 120 दिनों से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, इसलिए इसे खारिज किया जाना था। मैं इसमें दिए गए कारणों से सहमत हूं। इसके अलावा, यह पता चला है कि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है। ग्रेच्युटी राशि वितरित की गई है।

6. नीचे दिए गए मंचों के समक्ष कार्यवाही की जानकारी/सेवा के रूप में, कोई ठोस कारण सामने नहीं आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के बारे में विधिवत नोटिस दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित होने या जवाब देने में विफल रहा। यह उचित परिश्रम की कमी को दर्शाता है, और परिणामी एकपक्षीय आदेश उनकी लापरवाही, उनकी अपनी करतूत का परिणाम था, न कि प्रक्रियागत चूक का। कानून या कार्यवाही की अज्ञानता बचाव नहीं हो सकती, खासकर

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)

एक शैक्षणिक संस्थान के लिए जिससे कानूनी ढांचे के भीतर काम करने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत स्वीकार्य 120-दिन की सीमा से परे अपील दायर करने में देरी की।

7. गुण-दोष के आधार पर, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"4. ग्रेच्युटी का भुगतान।*
>
> *(1) किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसके रोजगार की समाप्ति पर देय होगी, जब उसने कम से कम पांच वर्ष तक लगातार सेवा की हो, -*
>
> *(क) उसकी सेवानिवृत्ति पर, या*
>
> *(ख) उसकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर, या*
>
> *(ग) दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु या विकलांगता पर:*
>
> *बशर्ते कि पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु या विकलांगता के कारण हुई हो:*
>
> *इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसे देय ग्रेच्युटी उसके नामिती को या, यदि कोई नामिती नहीं किया गया है, तो उसके उत्तराधिकारियों को दी जाएगी, और जहां कोई नामिती या उत्तराधिकारी नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का हिस्सा, उसके खाते में जमा किया जाएगा। नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा करेगा जो उसे ऐसे अवयस्क के लाभ के लिए ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में निवेश करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि वह अवयस्क वयस्क न हो जाए।*
>
> *स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विकलांगता का अर्थ ऐसी विकलांगता है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए अक्षम कर देती है जिसे वह दुर्घटना या बीमारी से पहले करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी विकलांगता हुई।*

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)

x-x-x-x-x-x"

8. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के साथ धारा 124 के अवलोकन से, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मृतक कर्मचारी को ग्रेच्युटी राशि के भुगतान का हकदार माना गया था। इस आधार पर भी, गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

9. जैसा कि स्पष्ट है, ग्रेच्युटी का दावा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत शासित है, जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुगतान को अनिवार्य बनाता है। याचिकाकर्ता के पास दावे के खिलाफ कोई ठोस बचाव नहीं है, और यह याचिका केवल तुच्छ और बाधा उत्पन्न करने वाले मुकदमे में लिप्त होने के अलावा और कुछ नहीं है। इस मामले को आगे बढ़ाना केवल याचिकाकर्ता की मृतक कर्मचारी और अब उसकी विधवा के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के बजाय जवाबदेही से बचने की मंशा को दर्शाता है।

10. यह सुनने में भले ही घिसा-पिटा लगे, लेकिन ग्रेच्युटी कोई इनाम नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है और इसके भुगतान में देरी एक गंभीर उल्लंघन है। एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में, याचिकाकर्ता को जवाबदेही और जिम्मेदारी के उच्च मानकों पर रखा जाना चाहिए। उनके कार्य उनके नैतिक दायित्वों को कमजोर करते हैं और, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर उनकी निंदा नहीं की जाती है, तो इसी तरह के संस्थानों में एक प्रतिकूल मिसाल कायम होगी।

11. विदाई के समय, याचिकाकर्ता-संस्थान के विद्वान वकील का तर्क कि याचिकाकर्ता-संस्थान को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर नहीं सुना गया था, एक बार फिर से खारिज किया जाना चाहिए। इस स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैंने गुण-दोष के आधार पर तर्कों को विस्तार से सुना है। ऊपर दर्ज की गई मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, भले ही यह एक पक्षीय आदेश हो।

12. प्रतिवादीगण संख्या 4 के पति, जो कैंसर से पीड़ित थे, मुकदमे को शांत करने की उम्मीद में मर गए, जबकि याचिकाकर्ता-संस्थान ने बिना किसी सार के लगातार मुकदमा चलाया है। आखिरकार, यह उनकी विधवा है, जो कानूनी प्रतिनिधि के रूप में उनके मामले को आगे बढ़ा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा एक असाध्य रूप से बीमार

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)

कर्मचारी और अब उसकी विधवा के खिलाफ दायर किया गया अड़ियल मुकदमा करुणा की कमी को दर्शाता है, जो सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बनाए गए एक शैक्षणिक संस्थान के लिए विशेष रूप से गंभीर है। एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, याचिकाकर्ता से न केवल एक आदर्श नियोक्ता होने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि एक नेक वादी के रूप में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

13. उपर्युक्त के मद्देनजर, रिट याचिका प्रतिवादीगण संख्या 4 को देय 25,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज की जाती है।

14. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

4-एसकेएम/-

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त : हां / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(D.B. SAW/715/2025 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 27/05/2025 at 04:48:53 PM)